

1 पांचवीं तक मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

2 9वीं-12वीं तक स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगी। छात्र मनपसंद विषय चुन सकेंगे

3 आइआइटी जैसे संस्थानों में पढ़ सकेंगे सामाजिक विज्ञान जैसे विषय

4 2030 तक वही शिक्षक बनेगा जिसके पास 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एचआरडी मंत्रालय का नाम होगा शिक्षा मंत्रालय

इसी सत्र से बदलाव लागू करने की तैयारी

कालेजों में एक प्रवेश परीक्षा

फीस की सीमा भी होगी तय

विदेशी यूनिवर्सिटी के कैम्पस खुलेंगे

यूजीसी-एसआइसीटीई की जगह लेगा उच्चतर शिक्षा आयोग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

नई दिल्ली. पूरे देश में एक जैसी शिक्षाप्रणाली के अपने चुनावी वादे पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को 34 बरस बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत देशभर में उच्चशिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने और प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे कई प्रावधान हैं। वहीं, 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) का नाम बदल कर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह नाम दिया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि नई नीति का लक्ष्य होगा, 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारी से विद्यार्थी वंचित न हों, उनका समग्र विकास हो। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, 'डिजिटल शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीक फोरम (एनईटीएफ) का गठन होगा। आठ क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार की जाएगी।' विश्व के शीर्ष 100 विदेशी कॉलेजों को भारत में कैम्पस खोलने की छूट दी जाएगी।

पढ़ें कालेजों @ पेज 04

शिक्षा के नाम पर 'कैद' के खिलाफ थे गुरुदेव

@पटिलकपूर

उच्च शिक्षा देश में एक रेगुलेटर

कोर्स

केमिस्ट्री-मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग

- मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स लिया जा सकता है। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी, लेकिन नई नीति में ऐसा संभव होगा।
- अब केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग ली जा सकेगी।
- आइआइटी जैसे संस्थान कला और मानविकी के साथ समग्र व बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे।
- कला और मानविकी के छात्र विज्ञान भी सीख सकेंगे।

पाठ्यक्रम

नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय बहु-विषयक होंगे। सभी छात्र वोकेशनल विषय और सॉफ्ट स्किल पढ़ेंगे

स्कूली शिक्षा अंग्रेजी जरूरी नहीं

स्थानीयता

3 भाषा फार्मूला, 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में

- पांचवीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही करवाई जाएगी।
- शिक्षा में तीन भाषा के फार्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा।
- इसमें संस्कृत को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
- स्कूल से ले कर उच्च शिक्षा तक में इसे प्रमुखता से जगह दी जाएगी।
- छठी कक्षा से ही वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।

स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान की स्ट्रीम में बंटवारा नहीं होगा। छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहें ले सकते हैं।

रेगुलेशन

पाठ्यक्रम और फीस तय करने के लिए नियामक

- सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान मानदंड तय किए जाएंगे।
- इसका अर्थ यह है कि नियामक के फ्रेमवर्क में ही पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

शोध पर जोर

- उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध के केंद्र की श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। संस्थानों का दायरा बढ़ाया जाएगा।

एडमिशन

एनटीए कराएगा प्रवेश परीक्षा, एमफिल खत्म

- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों या कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी।
- यह परीक्षा एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) लेगी। इस एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है।
- एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया। शोध के लिए एमफिल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अब तक एमफिल पीएचडी और परास्नातक के बीच की सीढ़ी मानी जाती थी।

लीगल व मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा।

एग्जाम

बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न, छठी से वोकेशनल शिक्षा

- बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव आएगा।
- सीबीएसई की बात करें तो गणित विषय की तरह, सभी विषय दो भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे।
- राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग को जांचने पर आधारित होंगी, न कि रटने की क्षमता पर।
- हर विषय के लिए वस्तुगत और विवरणात्मक, दोनों तरह की परीक्षाएं होंगी।

कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व इंटरशिप। मिलेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसी कक्षा से कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे।

असेसमेंट

रिपोर्ट कार्ड में शिक्षक व साथियों का मूल्यांकन भी

- प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री संपूर्ण होगा।
- रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा, साथियों और छात्रों द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा।
- इसका मकसद छात्रों के लर्निंग आउटपुट के साथ संपूर्ण विकास का मूल्यांकन होगा।
- क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न संवर्धन गतिविधियों के लिए बिना बस्ते वाले दिन (बैगलेस डेज) को प्रोत्साहन